CONGRESS

आरटीआई का प्रभाव

- आरटीआई ने नागरिकों को पहली बार इतनी जानकारी तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाया।
- नागरिक अब निष्क्रिय नहीं रह गए हैं और वे पहले से अधिक सक्षम हुए हैं और अपनी सरकार में बढ़ोत्तरी की माँग कर रहे हैं।
- पारदर्शी सरकार और लोकपाल आंदोलन के लिए चले आंदोलन साफ तौर पर आरटीआई का नतीजा हैं।

क्या आप जानते हैं?

- आप संवैधानिक अधिकारियों सहित किसी भी सरकारी अधिकारी से प्रश्न कर सकते हैं।
- आप किसी भी ऐसी सूचना तक पहुँच बना सकते हैं जो किसी सांसद की पहुँच में होती है।
- अब आपकी सरकार अपने नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेह है।

यह सब अब आपका अधिकार है

केवल एक ऐसी पार्टी जिसको विश्वास है कि उसके पास कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है, जो नागरिकों की सर्वोच्चता में विश्वास करती है, ऐसा कानून बना सकती है, और कांग्रेस पार्टी ने, संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार के नेतृत्व में ऐसा किया है।

सूचना का अधिकार कानून, 2005, कांग्रेस पार्टी ने आपको सुलभ कराया है

CONGRESS

आरटीआई आवेदन करने की प्रक्रिया :

- कोई भी व्यक्ति पीआईओ (जन सूचना अधिकारी) के पास लिखित अनुरोध जमा करके सूचना के लिए आवेदन कर सकता है। इस कानून के तहत अनुरोध करने वाले भारत के किसी भी नागरिक को सूचना प्रदान करने के लिए पीआईओ बाध्य है।
- अगर अनुरोध किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण (पूर्णतः या अंशतः) से संबंधित है, तो यह पीआईओ की ज़िम्मेदारी है कि वह अनुरोध के संबंधित हिस्सों को अन्य पीआईओ के पास 5 कार्यदिवस के भीतर हस्तांतरित/अग्रेषित करे।
- इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सरकारी अधिकारी को सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) की नियुक्ति करनी चाहिए जो आरटीआई अनुरोध और अपील स्वीकार करे और अपने सरकारी अधिकारी को अग्रेषित करे।
- सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने नाम और संपर्क विवरणों के अलावा कोई भी अन्य जानकारी या कारण प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है।